समक्ष एम. एम. पंच्ही, न्यायाधीश।

पियारा सिंह और दूसरा,—अपीलकर्ता।

बन्दी सेंट्रल बैंक और अन्य,—प्रतिद्वंद्वी।

सिविल संशोधन संख्या 1985 का 194

20 दिसंबर, 1985

नागरिक प्रक्रिया संहिता (1908 का अनुच्छेद V)— आदेश XXI, नियम 89 और 92— एक अदालती आदेश के अधीन अचल संपत्ति की बिक्री—न्याय आदेश से बिक्री को निरस्त करने के लिए न्याय ऋणी द्वारा नियम 89 के तहत एक आवेदन दाखिल करना—आवेदन के साथ आवश्यक जमा— ऐसा आवेदन—क्या वापस लिया जा सकता है— नियम 89 के तहत आवेदन को स्वीकृत करने के लिए आदेश—बिना नोटिस के बिक्री के आयोगपक्ष को देने के लिए क्या किया जा सकता है।

निर्णय, कि एक बार यदि आवेदन किसी योग्य व्यक्ति द्वारा नियम 89 के तहत नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXI के अनुच्छेद में आता है और जैसा कि प्रत्यारोपित किया गया था, तो जमा की गई धनराशि आवेदक की धनराशि या उस न्यायाधीश की धनराशि नहीं रहती थी, अगर वह आवेदक था। नियम 89 के तहत एक आवेदन दाखिल करने से कोई मुकदमा नहीं शुरू होता है, बल्कि उक्त नियम के तहत आवेदन का स्पष्ट उद्देश्य होता है कि अदालती बिक्री के खिलाफ एक चुनौती को समाप्त किया जाए, लेकिन, उसी समय, जमा की गई धनराशि से न्यायाधीश को भुगतान के लिए और नीलामी खरीददार को मुआवजे के लिए समय पर नकदी की गई। ऐसी धनराशि के जमा होने पर, आवेदक ने अपने आप को नीलामी खरीददार के जूते में रख दिया, क्योंकि उसने केवल 5 प्रतिशत की खरीद की कीमत के बराबर राशि का भुगतान करके सीधे उसे संतुष्ट किया था, बल्कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से न्याय धारी भी संतुष्ट किया, जो पहले में ही खरीदने वाले द्वारा किये जाने वाले भुगतान के द्वारा संतुष्ट होने का साहस किया गया था। व्यक्तिगत लड़ाई होते समय, ऐसे परिस्थितियों में अदालत के पास आवश्यकता का कोई विकल्प नहीं होता है, केवल यही एक विकल्प होता है जो नियम के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा। ऐसा अचानकता को छोड़कर अदालत का नियम भी इस नियम के उद्देश्य के साथ मेल खाता है कि इसमें दो रास्ते नहीं हैं, जो यह नियम के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा। ऐसे कानूनी आदेश में उसकी विरोधिता का प्रतिबंध लगाना जो आवेदक पर लगाया जाता है कि, उसके आवेदन को केवल अगर यह नियम में उचित और वैध रूप से किया गया था, और जरूरी जमा के साथ, उसका आवेदन वापस नहीं किया जा सकता था। इस तरह से, आदेश XXI, नियम 89 के तहत किया गया आवेदन वापस नहीं लिया जा सकता है जब तक कि, बेशक, आवेदन व्यवस्थित और वैध रूप से नहीं किया गया था, आवश्यक जमा के साथ और उसका अगर नहीं, तो वह ठुकराया जा सकता था।

(पैरा 12)

निर्णय, कि नियम 89 के तहत दाखिल किए गए आवेदन को स्वीकार करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है जब तक इस आवेदन की सूचना सभी इससे प्रभावित व्यक्तियों को नहीं दी गई हो। इस सिद्धांत के लिए काफी प्राधिकरण है कि नीलामी खरीददार भी उन्हीं व्यक्तियों में से एक हैं जिन्हें इससे प्रभावित किया गया है, क्योंकि स्पष्ट रूप से उस नियम के तहत, उसके लिए खरीद की कीमत के बराबर राशि की गारंटी होती है। इसलिए, उसे आवेदन में या जमा की माप में दोषों की इशारा करने का अधिकार होता है। लेकिन उसकी भागीदारी बहुत सीमित है और केवल इस उद्देश्य के लिए है, कि वह इस प्रकार प्रभावित न हो, जिसमें उसका अधिकार नियमों के तहत किसी भी प्रकार से खतरे में हो। यदि उसे नियम 89 के अधिकारों से लाभों को त्याग करना पड़ता था और उसी समय नीलामी के लाभों को भी छोड़ना पड़ता था, तो यह कानून की भावना के खिलाफ होगा। इसलिए, इस सीमित उद्देश्य के लिए, उसकी भागीदारी, जब तक कि अदालत द्वारा उसकी आवश्यकता को और भी स्पष्ट कर दिया गया है, आवश्यक है, और यह मतलब है कि, हालातों में अदालत को इस आवेदन को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वह भी तुरंत, लेकिन यह आपत्ति के साथ संरक्षित है कि प्रभावित पक्ष जिसका मतलब है नीलामी खरीददार, को आवेदन की सूचना दी गई है, ताकि उसे यह जागरूक किया जा सके कि उसे नियम 89 के तहत मुआवजा दिया जा रहा है और कि अदालत, सौदा वापसी के अधिकार को भी ध्यान में रखते हुए, फॉर्मल आदेश पास करेगी। नियम 89 को इसी तरह से ही एक साथ मेल-मिलाप किया जा सकता है ताकि इसका उद्देश्य पूरा हो सके। (पैरा 13)

नियम 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री बी.आर. वोहरा की अदालत के आदेश को संशोधित करने के लिए। दिनांक 15 नवंबर, 1984 को। जो कि श्री वी.पी. चौधरी की अदालत के, हिसार के उप जिला न्यायाधीश श्री धनी राम यादव, पहली श्रेणी, की तारीख 18 जनवरी, 1983 को पारित कर रहा था, अपील को स्वीकार करते हुए और मामले को पुनर्निर्देशित करते हुए प्रायोगिक न्यायालय (श्री धनी राम यादव, पहली श्रेणी, हिसार) के सामने पक्षों को दिशा देते हुए, उनके वकील के माध्यम से।

एच. एल. सिब्बल, वरिष्ठ प्रवक्ता सहित एस. सी. सिब्बल-प्रावक्ता और आर.के. हंडा, प्रावक्ता, प्रार्थी के लिए।

आर.के. अग्रवाल, प्रावक्ता संख्या 1 के लिए। नगिंदर सिंह, प्रावक्ता संख्या 4 के लिए। एन.सी. जैन, वरिष्ठ प्रवक्ता सहित वी.के. जैन, प्रतिद्वंद्वी के लिए।

न्याय

एम.एम. पुंछी, जे.:- जैसा कि सर्वविदित है, सिविल प्रक्रिया संहिता जो इस देश में नागरिक मुकदमे के तरीके को नियंत्रित करती है, काफी हद तक प्रतिकूल प्रणाली पर आधारित है। यह प्रणाली, जैसा कि स्पष्ट है, पार्टियों को लड़ाई में डाल देती है और

न्यायालय तब, बड़े पैमाने पर, अन अंपायर की भूमिका ग्रहण करता है। अक्सर यह देखा गया है कि यदि कोई प्रतिद्वंद्वी हार मान लेता है, खेल रोक देता है या बाहर चला जाता है, तो अंपायरिंग की भूमिका भी समाप्त हो जाती है और युद्ध के मैदान में डटे हुए प्रतिद्वंद्वी को, परिणामस्वरूप, जो कुछ भी उसका हक होता है, वह मिल जाता है। अब, क्या ये सिद्धांत आदेश XXI, नियम 89 और 92 की व्याख्या को प्रभावित करते हैं, और यदि हां, तो किस हद तक, यह सूक्ष्म प्रश्न है जो इस पुनरीक्षण याचिका में उठा है। इससे संबंधित आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं:-

2. सेंट्रल बैंक भारत रुपये की वसूली के लिए मनी डिक्री प्राप्त की। 37,753.26 पी. मोहिंदरसिंहके खिलाफ 11 जनवरी, 1979 को प्रतिवादी। डिक्री-धारकसेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 26 फरवरी, 1982 को एक विवाहित जोड़े हरि किशन और सोमा वंती के पक्ष में डिक्री स्थानांतरित कर दी। अंतरिती-डिक्री-धारकों ने डिक्री को निष्पादित करने के लिए एक निष्पादन याचिका निकाली और उसके निष्पादन में भूमि का एक टुकड़ा स्पष्ट रूप से मोहिंदर सिंह का था। निर्णय- देनदार को कुर्क किया गया और फिर 3 जनवरी, 1983 को नीलामी द्वारा बेच दिया गया। चार दिन बाद 7 जनवरी, 1983 को मोहिंदर सिंह ने के तहत आपत्तियां दायर कीं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 निष्पादन याचिका को खारिज करने की प्रार्थना। उसके तीन दिन बाद 10 जनवरी, 1983 को, मोहिंदर सिंह ने अदालत से एक लिखित अनुरोध किया कि उनके द्वारा देय डिक्रीटल राशि निर्धारित की जाए ताकि वह जमा कर सकें। वही और बिक्री को अलग रख दें। यह आदेश XXI, नियम 89, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए था। निष्पादन न्यायालय ने निर्णय-देनदार को जमा करने का निर्देश देने वाले अनुरोध को स्वीकार कर लिया। रु. 37,531.31 पी. 14 जनवरी, 1983 को या उससे पहले। लेकिन मोहिंदर सिंह ने दो दिन पहले 12 जनवरी, 1983 को वही राशि जमा कर दी। उसी दिन, निर्णय-देनदार ने नीलामी-क्रेता को नोटिस के बाद बिक्री को रद्द करने के लिए आदेश XXI, नियम 89, सिविल प्रक्रिया संहिता, के तहत एक औपचारिक आवेदन किया। डिक्री धारक. निष्पादन न्यायालय ने 15 जनवरी, 1983 के लिए इस आवेदन का नोटिस जारी किया। फिर भी एक और आवेदन मोहिंदर सिंह< द्वारा दायर किया गया था। /span>सिंह निर्णय-ऋणी केवल एक था बेनामीदार. उन्होंने प्रार्थना की कि मोहिंदरसिंह और किशन चंद, वर्तमान पुनरीक्षण याचिकाकर्ता, चले गए निष्पादन न्यायालय के समक्ष एक याचिका में दावा किया गया कि वे वास्तव में उस भूखंड के मालिक थे जिसे नीलामी के लिए रखा गया था और मोहिंदर सिंहपियारा 18 जनवरी, 1983 को ऋणी का निर्णय, निष्पादन न्यायालय से मांग की गई कि उसके द्वारा पहले की तारीख से पहले दायर किए गए सभी आवेदन/आपत्तियों को वापस ले लिया गया माना जाए और नीलामी के पक्ष में संपत्ति की बिक्री की पुष्टि की जाए- क्रेता. हालाँकि, उसी दिन यानी 18 जनवरी, 1983 को, इसे वापस लेने और डिक्रीधारक को भुगतान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसके बाद बिक्री को रद्द कर दिया जाएगा और निष्पादन याचिका पूरी तरह से संतुष्ट होने पर भेज दी जाएगी। निष्पादन न्यायालय ने उसी दिन 18 जनवरी, 1983 को दोनों आवेदनों का निपटारा यह मानते हुए किया

कि चूंकि न्यायालय का कार्य निष्पादन के माध्यम से डिक्री को संतुष्ट करना था और डिक्री की राशि जमा कर दी गई थी, इसलिए डिक्री संतुष्ट थी और इस प्रकार रद्द कर दी गई। नीलामी बिक्री ने निर्णय-देनदार और वर्तमान याचिकाकर्ताओं-आपत्तिकर्ताओं के लिए उचित मंच पर प्रश्नगत भूखंड पर अपने अधिकारों का निपटान करने के लिए इसे खुला छोड़ दिया, क्योंकि उनका विचार था कि उनके विवाद का निष्पादन आवेदन के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं है।

3. नीलामी-खरीदार ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, हिसार के समक्ष कार्यकारी न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर की, लेकिन वर्तमान याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी के रूप में शामिल किए बिना। मोहिंदरसिंह निर्णय-देनदार ने भी अपील दायर की लेकिन उन्होंने उत्तरदाताओं को फंसाने में सावधानी बरती। दोनों अपीलों को समेकित किया गया और श्री बी.आर.वोहरा, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, हिसार द्वारा एक सामान्य आदेश द्वारा निपटारा किया गया। उन्होंने निष्पादन न्यायालय के आदेश को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि मोहिन्दरसिंह निर्णय-देनदार को किसी भी कानून के तहत 12 जनवरी की अपनी पिछली याचिका वापस लेने से नहीं रोका गया था। 1983 की प्रस्तावना के रूप में उन्होंने डिक्रीटल राशि और खरीद राशि का पांच प्रतिशत जमा कर दिया था क्योंकि उनका निकासी आवेदन नीलामी की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति से पहले किया गया था जिसके बाद बिक्री की पुष्टि की जानी थी। उन्होंने आगे यह विचार रखा कि आदेश XXI, नियम 89, सिविल प्रक्रिया संहिता, के प्रावधान केवल निर्णय-देनदार को डिक्रेटल जमा करने की रियायत थे बिक्री की पुष्टि होने से पहले राशि आदि और रियायत का लाभ उठाने या इससे हटने का फैसला निर्णय-देनदार पर निर्भर करता है। अंतिम निष्कर्ष में, यह विचार किया गया कि आदेश XXI, सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 92 के उप-नियम (2) के तहत, मोहिंदर के आवेदन < /span> निर्णय-ऋणी और वर्तमान आपत्तिकर्ता-याचिकाकर्ता, दोनों दिनांक 18 जनवरी, 1983 को केवल तभी निर्णय लिया जा सका जब प्रभावित सभी पक्षों को नोटिस दिया गया था, और चूंकि ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने मामले की जांच करने और उस पर कानून के अनुसार निर्णय देने के लिए निष्पादन न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया। इस आदेश को चुनौती देने के लिए, आपत्तिकर्ता-याचिकाकर्ताओं ने पुनरीक्षण के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और जैसा कि ऊपर बताया गया है, न्यायशास्त्रीय प्रश्न निर्धारण के लिए सामने आया है।सिंह

4. आम तौर पर, जब कोई व्यक्ति सिविल कोर्ट में कोई मामला दायर करता है, तो उसे इसे वापस लेने और फिर इसके परिणाम भुगतने का अधिकार होता है। पहली नज़र में, व्यक्ति आदेश XXI, नियम 89, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक आवेदन पर भी यही सिद्धांत लागू करेगा, जिसमें बिक्री को रद्द करने के लिए एक आवेदन प्रदान किया जाएगा। जमा पर. वह नियम इस प्रकार है:—

“89. जमा राशि पर बिक्री को अलग करने के लिए आवेदन,-

(1) जहां डिक्री के निष्पादन में अचल संपत्ति बेची गई है, बिक्री के समय या आवेदन करने के समय या ऐसे व्यक्ति के लिए या उसके हित में कार्य करने के समय बेची गई संपत्ति में हित का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है न्यायालय में जमा करने पर उसे अलग रखा जाए, -

(ए) क्रेता को भुगतान के लिए, खरीद धन के पांच प्रतिशत के बराबर राशि, और

(बी) डिक्री-धारक को भुगतान के लिए, बिक्री की उद्घोषणा में निर्दिष्ट राशि, जिसकी वसूली के लिए बिक्री का आदेश दिया गया था, बिक्री की ऐसी उद्घोषणा की तारीख के बाद से प्राप्त की गई किसी भी राशि को घटाकर डिक्री धारक.

(सी) जहां कोई व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति की बिक्री को रद्द करने के लिए नियम 90 के तहत आवेदन करता है, वह तब तक नहीं होगा, जब तक कि वह अपना आवेदन वापस नहीं ले लेता, इस नियम के तहत आवेदन करने या मुकदमा चलाने का हकदार नहीं होगा।

(डी) इस नियम में कुछ भी निर्णय-देनदार को बिक्री की उद्घोषणा द्वारा कवर नहीं की गई लागत और ब्याज के संबंध में किसी भी दायित्व से राहत नहीं देगा।

5. इसके बाद नियम 90 आता है जिसके तहत अनियमितता या धोखाधड़ी के आधार पर बिक्री को रद्द करने का आवेदन डिक्री-धारक या क्रेता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो संपत्ति के किसी भी प्रतिशोध योग्य वितरण को साझा करने का हकदार है या जिसके हित प्रभावित होते हैं। बिक्री द्वारा. यह आवेदक केवल तभी सफल हो सकता है जब वह न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह साबित कर सके कि ऐसी अनियमितता या धोखाधड़ी के कारण उसे पर्याप्त चोट लगी है। इसके बाद नियम 91 का पालन होता है जिसके तहत ऐसी किसी भी बिक्री पर क्रेता अदालत में इस आधार पर बिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है कि निर्णय-देनदार का बेची गई संपत्ति में कोई बिक्री योग्य हित नहीं था। इसके बाद नियम 92 का अनुसरण किया जाता है जिसके खंड (1) और (2) वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक होने के कारण इसके बाद पुनः प्रस्तुत किए जाते हैं: -

"92. बिक्री कब पूर्ण हो जाए या अलग कर दी जाए।

(1) जहां नियम 89, नियम 90 या नियम 91 के तहत कोई आवेदन नहीं किया जाता है, या जहां ऐसा आवेदन किया जाता है और अस्वीकार कर दिया जाता है, न्यायालय बिक्री की पुष्टि करने वाला एक आदेश देगा, और उसके बाद बिक्री पूर्ण हो जाएगी:

बशर्ते कि, जहां किसी भी संपत्ति को किसी दावे के अंतिम निपटान या ऐसी संपत्ति की कुर्की पर किसी आपत्ति के लंबित रहने तक किसी डिक्री के निष्पादन में बेचा जाता है, तो न्यायालय ऐसे दावे या आपत्ति के अंतिम निपटान तक ऐसी बिक्री की पुष्टि नहीं करेगा।

(2) जहां ऐसा आवेदन किया जाता है और अनुमति दी जाती है, और जहां, नियम 89 के तहत किसी आवेदन के मामले में, उस नियम द्वारा आवश्यक जमा बिक्री की तारीख से तीस दिनों के भीतर किया जाता है, या ऐसे मामलों में जहां नियम के तहत जमा की गई राशि यदि जमाकर्ता की ओर से किसी लिपिकीय या अंकगणितीय गलती के कारण धारा 89 में कमी पाई जाती है और ऐसी कमी को न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर पूरा कर दिया गया है, तो न्यायालय बिक्री को रद्द करने का आदेश देगा:

बशर्ते कि कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आवेदन की सूचना उससे प्रभावित सभी व्यक्तियों को न दे दी गई हो।

6. उपरोक्त नियमों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री एच.एल. सिब्बल ने तर्क दिया कि एक बार जमा पर बिक्री को रद्द करने के लिए एक आवेदन आदेश XXI, नियम 89, सिविल प्रक्रिया के तहत किया गया था। कोड,और जब न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि उस नियम के तहत आवश्यक जमा बिक्री की तारीख से तीस दिनों के भीतर किया गया है, या ऐसे मामलों में जहां नियम के तहत जमा की गई राशि पाई जाती है जमाकर्ता की ओर से किसी लिपिकीय या अंकगणितीय गलती के कारण कमी हो गई है और ऐसी कमी को न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर पूरा कर दिया गया है, न्यायालय के पास आवेदन स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, न्यायालय के एकमात्र उद्देश्य के लिए डिक्री को निष्पादित करना है, जो निर्णय-देनदार द्वारा उठाए गए कदम से आसानी से संभव हो जाता है, जिससे न्यायालय को अपनी भूमिका समाप्त करनी पड़ती है। इसके अलावा उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि आदेश XXI, नियम 89, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत किसी भी आवेदन को किसी भी स्थिति में अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, अनुमति तो बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है। वापस ले लिया गया, जब नियम की सभी आवश्यक बातें जैसे कि उसमें कल्पना की गई जमा राशि, एक नीलामी-क्रेता के लिए और दूसरा डिक्री-धारक के लिए, नीलामी-बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए बनाई गई है।

7. दूसरी ओर, नीलामी-क्रेता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री एन.सी. जैन ने तर्क दिया कि आदेश XX, नियम 89, C.P.C, के तहत एक आवेदन निर्णय देनदार के एकतरफा कार्य द्वारा वैध रूप से वापस लिया जा सकता था; और न्यायालय को जो कुछ करना था वह औपचारिक वापसी की अनुमति देना था और जैसे ही न्यायालय को इस संबंध में सूचना दी गई, वापसी का कार्य पूरा हो गया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि न्यायालय आदेश XXI, नियम 89, C.P.C, के तहत आवेदन स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी मामले में, इसकी स्वीकृति से पहले, अपेक्षित आदेश XXI, सी.पी.सी. के नियम 92 के प्रावधानों के तहत नीलामी-क्रेता को नोटिस देना जरूरी था

8. निर्णय-ऋणी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सरदार नागेंदर सिंह ने उस भूखंड की पहचान के संबंध में विवाद उठाया जिसके साथ निर्णय-ऋणी ने बातचीत की थी।

याचिकाकर्ता. उन्होंने श्री जैन के तर्कों का समर्थन करते हुए कहा कि निर्णय-देनदार को आदेश XXI, नियम 89, के तहत आवेदन वापस लेने का अधिकार है। सी.पी.सी

9. पक्षों के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत मामले के कानून का अब जायजा लिया जा सकता है। बहुत पहले, कुमुकुट्टी बनाम मन्नोदथ (1) में मद्रास उच्च न्यायालय की एकल पीठ थी नेआदेश XXI के दायरे को समझते हुए , नियम 89, सी.पी.सी.,इस प्रकार मनाया गया:—

"लेकिन 0.21, आर. 89, एक विशेष प्रावधान अधिनियमित करता है। इसका उद्देश्य हर तरह के झगड़े और विवाद को ख़त्म करना है. निर्णय-देनदार को उसकी संपत्ति के खतरे से वंचित होने से बचाया जाता है; डिक्री-धारक का दावा संतुष्ट हो जाता है और नीलामी-खरीदार को मुआवजा दिया जाता है। यदि इसके तहत पैसा देने वाले व्यक्ति को विरोध के तहत ऐसा करने की अनुमति दी गई तो यह वर्ग निराश हो जाएगा। (तब नियम 89 का C1 (2) उद्धृत किया गया था)। इससे पता चलता है कि इस खंड में उल्लिखित दो कार्यवाहियाँ पूरी तरह से असंगत हैं। यदि देनदार किसी विवाद को खुला रखना चाहता है, तो वह इस धारा के लाभ का दावा नहीं कर सकता है। वास्तव में, यह उसे एक विशेष अनुग्रह प्रदान करता है। हालाँकि इस प्रकार उसका पक्ष लिया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाता है कि न तो डिक्रीधारक और न ही क्रेता के हितों का बलिदान किया जाए। इससे यह पता चलता है कि जब निर्णय-देनदार निर्दिष्ट राशि का भुगतान करता है, तो वह इसे बिना शर्त भुगतान करता है।'

उपरोक्त दृष्टिकोण को मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने एल.ए. कृष्णा अय्यर बनाम अरुनाचाल्लम चेत्तिअर (2) पूर्ण पीठ के आधिपत्य ने इस विषय पर संपूर्ण मामले के कानून पर विचार किया और निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"निर्णय-देनदार या संपत्ति में रुचि रखने वाला व्यक्ति आदेश 21, नियम 89 और के तहत अपनी जमा राशि में कोई शर्त नहीं लगा सकता है। न्यायालय किसी भी शर्त या विरोध के अधीन जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकता। एक बार जब आवेदन करने के हकदार व्यक्ति द्वारा उचित राशि जमा कर दी जाती है, तो अदालत के पास बिक्री को रद्द करने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है;****

मैं उस राय से सहमत हूं जो मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से सही है क्योंकि नियम 89 में कोई जांच शामिल नहीं है लेकिन नियम 90 में शामिल है और उस जांच के परिणामस्वरूप आवेदन खारिज हो सकता है, जबकि पूर्व नियम अदालत को इसे रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं देता है। बिक्री करना।"

(जोर दिया गया)

कांडा वेलू बनाम कुमारन गोविदन (3) उस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने भी यह देखते हुए यही दृष्टिकोण अपनाया। जब एक जमा और एक आवेदन उचित रूप से आदेश 21, नियम 89 के तहत किया जाता है, तो आवेदन करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा कोर्ट-

सेल को अलग करने के लिए और समय के भीतर, न्यायालय के पास कोई विकल्प नहीं है और वह बिक्री को रद्द करने के लिए बाध्य है। हालाँकि, उस मामले में, एक नियम के रूप में, यह तय कर लिया गया था कि नीलामी-क्रेता को नोटिस के बाद आवेदन की अनुमति दी जा सकती है यदि उसे पहले से ही आवेदन दाखिल करने के बारे में पता नहीं था।

10. राम चंद्र v में। नारायण पार्षद (4) पर जोर दिया गया था और यदि आवेदक संपत्ति में रुचि का दावा करता है आदेश XXI, नियम 89, के तहत आवेदन करने का समय, नीलामी-क्रेता को भुगतान के लिए खरीद मूल्य का 5 प्रतिशत और राशि न्यायालय में जमा करना डिक्री-धारक के कारण, वह बिक्री को रद्द करने का हकदार था।

11. इन इत्तियाथी गोपालन v. नानी अम्मा अम्मुकुट्टी अम्मा (5) की प्रकृति का निर्धारण करते हुए उस न्यायालय की एक डिविजन बेंच आदेश XXI, नियम 89, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत जमा राशि पर विचार किया गया कि ऐसा पैसा निर्णय-देनदार का नहीं था और इस प्रकार था , उसकी कोई संपत्ति नहीं, जिसे उसके लेनदारों के बीच उचित रूप से वितरित किया जा सके। उनके आधिपत्य ने देखा कि अब से जमा राशि केवल डिक्री-धारक की थी। नियम 89 के आयात के संबंध में, यह निम्नानुसार देखा गया:

"आदेश 21 नियम 89, के तहत आवेदनों के अनुसरण में कार्यवाही इस आधार पर आगे बढ़ें कि निष्पादन बिक्री धोखाधड़ी और अन्य से प्रभावित न हो परिस्थितियों को खराब करने वाला और संपत्ति पर वैध और बाध्यकारी है।

और जब आदेश 21, नियम 89 के तहत जमा किया जाता है और उस नियम के तहत एक आवेदन की अनुमति दी जाती है, तो क्या होता है प्रभाव, नीलामी-क्रेता के अधिकारों का आवेदक को हस्तांतरण है

में शिव प्रसाद v. दुर्गा प्रसाद (6) उनका प्रभुत्व इस प्रकार देखा गया:—

"आवेदक को अदालत को केवल यह बताना होगा कि वह नियम 90 के तहत अपना आवेदन वापस ले रहा है, जिसे उसने नियम 89 के तहत आवेदन करने से पहले दायर किया था, जिसके बाद वह बाद वाला आवेदन करने का हकदार हो जाता है। प्रत्येक आवेदक को अपना आवेदन बिना शर्त वापस लेने का अधिकार है और इस संबंध में उसका एकतरफा कार्य पर्याप्त है। उसे आवेदन वापस लेने की अनुमति देने के लिए न्यायालय का कोई आदेश आवश्यक नहीं है। न्यायालय आवेदन को वापस लिए गए रूप में निस्तारित करने का औपचारिक आदेश दे सकता है लेकिन वापसी न्यायालय के आदेश पर निर्भर नहीं है। जैसे ही आवेदक अदालत को सूचित करता है कि उसने आवेदन वापस ले लिया है, वापसी की कार्रवाई पूरी हो जाती है।"

और आखिरी मामला वह है जिस पर उत्तरदाताओं के विद्वान वकील इस तर्क पर भरोसा करते हैं कि नियम 89 के तहत एक आवेदन भी एकतरफा वापस लेने योग्य है। पक्षों के

विद्वान वकील द्वारा उद्धृत अन्य सभी उदाहरण मुझे मुद्दे से परे लगते हैं और इस फैसले पर बोझ डालने की जरूरत नहीं है।

12. अब सबसे पहले शुरू में पूछे गए प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उस संदर्भ में पहले यह निर्धारित करना होगा कि नियम 89 के तहत कोई आवेदन वापस लेने योग्य है या नहीं। इस विषय पर पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मैं इस विचार पर आया हूं कि ऐसा नहीं है। एक बार जब यह पता चल जाता है कि आवेदन उस नियम के दायरे में आने वाले एक उचित व्यक्ति द्वारा किया गया था और उसके साथ परिकल्पना के अनुसार जमा राशि भी शामिल थी, तो जमा की गई धनराशि आवेदक या निर्णय-देनदार की धनराशि नहीं रह जाती है, यदि वह आवेदक था. इत्तियाथी गोपालन के मामले में त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार (सुप्रा) मुझे सही और स्वीकार्य लगता है, खासकर जब यह पटना उच्च न्यायालय के एक फैसले पर आधारित था, जिसे v. कालंदी सेंदा (7) उसमें निर्धारित नियम अन्यथा अच्छा अर्थ रखता है। नियम 89 के तहत आवेदन दाखिल करने से कोई कारण स्थापित नहीं होता है, बल्कि उक्त नियम के तहत आवेदन कोर्ट-सेल की चुनौती को समाप्त करने के स्पष्ट उद्देश्य से किया जाता है, लेकिन साथ ही, समय पर जमा द्वारा इसकी पुष्टि से बचा जाता है। डिक्री-धारक को भुगतान के लिए और नीलामी-क्रेता को मुआवजे के भुगतान के लिए धन का। ऐसे पैसे जमा करने पर, आवेदक खुद को नीलामी-क्रेता के स्थान पर रखता है, क्योंकि उसने खरीद मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करके न केवल सीधे तौर पर उसे संतुष्ट किया है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से डिक्री-धारक को भी संतुष्ट किया है। वह भी, जिसने पहली बार में, क्रेता द्वारा किए जाने वाले संभावित भुगतान से संतुष्ट होने का साहस किया था। स्पष्ट रूप से, उन परिस्थितियों में जब प्रतियोगिता पीछे हट जाती है, न्यायालय के पास एक बार में आवेदन की अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, जैसा कि एल.ए. कृष्णा अय्यर के मामले (सुप्रा) में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने माना था। न्यायालय द्वारा इस तरह की अचानक छोड़ी गई टिप्पणी भी नियम की भावना के अनुरूप है कि इसके लिए कोई दो रास्ते नहीं हैं सिवाय एक के जो नियम के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा। कानून के इस तरह के आदेश में आवेदक पर यह निषेध लगाया गया है कि, उसका आवेदन कानून में उचित होने और अपेक्षित जमा राशि के साथ होने पर, उसका आवेदन वापस लेने में सक्षम नहीं है। इस अर्थ में यह हितकारी नियम अन्य अच्छी तरह से उपयोग किए जाने वाले नियमों का अपवाद है, जिसमें विरोधी प्रणाली में काम करने वाले वापसी के नियम भी शामिल हैं। इस प्रकाश से देखने पर, शिव प्रसाद के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ, जैसा कि मुझे लगता है, नियम 89 के तहत किसी आवेदन पर लागू नहीं होती हैं और न ही लागू हो सकती हैं, क्योंकि, यह स्पष्ट रूप से एक चिह्नित अपवाद है सामान्य नियम के लिए. इस प्रकार, मेरा मानना है कि आदेश XXI नियम 89 के तहत किया गया एक आवेदन,जब नियम 92 के आलोक में पढ़ा जाता है, तो यह वापस लेने योग्य नहीं है, बशर्ते कि आवेदन सही ढंग से और वैध तरीके से किया गया हो, अपेक्षित जमा राशि के साथ, और यदि ऐसा नहीं है, तो यह अस्वीकार्य है।

13. अब, आदेश XXI, सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 92(2), के प्रावधान पर आते हुए, यह ध्यान देने योग्य है कि इसके तहत आवेदन की अनुमति देने के लिए कोई आदेश नहीं है। नियम 89 तब तक बनाया जा सकता है जब तक कि इससे प्रभावित सभी व्यक्तियों को आवेदन की सूचना न दे दी गई हो। इस प्रस्ताव में काफी दम है कि नीलामी-खरीदार इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों में से एक है, जाहिर है, उक्त नियम के तहत, खरीद मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर राशि उसके लिए सुनिश्चित है। इस प्रकार, वह आवेदन में या जमा राशि के माप में दोष बताने का हकदार है। हालाँकि, उनकी भागीदारी बहुत सीमित है और केवल यह देखने के उद्देश्य से है कि वह इस तरह से प्रभावित न हों कि नियमों के तहत उनके अधिकार किसी भी तरह से खतरे में पड़ जाएँ। यह कानून की भावना के विपरीत होगा यदि वह नियम 89 के तहत उसे दिए गए लाभ और नीलामी के लाभ को एक ही समय में खो दे। इस प्रकार, इस सीमित उद्देश्य के लिए, न्यायालय द्वारा इस तरह के आवेदन को औपचारिक रूप से अनुमति देने से पहले उनकी भागीदारी आवश्यक है और, इस संदर्भ में, जैसा कि मैं समझता हूं, एल.ए. कृष्णा अय्यर के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का आदेश है। ;के मामले (सुप्रा) का मतलब है कि, हालांकि अदालत के पास आवेदन की अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और वह भी एक बार में, लेकिन यह आरक्षण के अधीन है कि प्रभावित पक्ष, जिसका अर्थ है नीलामी-खरीदार, को नोटिस दिया गया है आवेदन का ताकि उसे पता चले कि उसे नियम 89 के तहत मुआवजा दिया जा रहा है और अदालत, औपचारिक आदेश पारित करते हुए, उसे नियम 93 के तहत खरीद के पैसे वापस करने का भी हकदार मानेगी। यह केवल उसके तरीके में है कि नियम 89 को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जा सकता है।

14. अब, मामले के तथ्यों पर आते हैं, तो स्पष्ट रूप से नीलामी-क्रेता को नहीं सुना गया था जब अदालत ने 18 जनवरी, 1983 को आवेदन की अनुमति दी थी, मोहिंदरसिंह को अनुमति नहीं दी थी। उक्त नियम के तहत आवेदन और जमा राशि वापस लेने के लिए। इस प्रकार, इस अर्थ में, निष्पादन न्यायालय आंशिक रूप से सही और आंशिक रूप से गलत था। पिछले पैराग्राफ में विषय पर कानून की व्याख्या करने के बाद, मोहिंदर के आदेश XXI, नियम 89, सी.पी.सी. के तहत आवेदन सिंह को अब निष्पादन न्यायालय द्वारा नीलामी-क्रेता की उपस्थिति में निपटाया जाएगा, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से अब आवेदन की सूचना है क्योंकि वह इसके बारे में जानता है।

15. अंत में, पक्षों के विद्वान वकील के प्रति निष्पक्ष होने के लिए, मुझे यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा इस आधार पर पुनरीक्षण याचिका की विचारणीयता पर आपत्ति उठाई गई थी कि याचिकाकर्ताओं के पास कोई लोकस-स्टैंड नहीं था। इसे बनाए रखने के लिए, लेकिन, जब उनका सामना इस प्रस्ताव से हुआ कि यह न्यायालय स्वत: संज्ञान लेकर आदेश को संशोधित कर सकता था, तो आपत्ति की आवाज को दब जाने दिया गया। इसी प्रकार, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की आपत्ति कि नीलामी-क्रेता एक व्यथित दयावान नहीं था, जो निष्पादन न्यायालय के आदेश को अपील में

चुनौती देने का हकदार था, को भी विशिष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। आदेश XXI, सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 92(2) का परंतुक। ऊपर उल्लिखित आपत्ति और प्रतिआक्षेप इस प्रकार समाप्त हो गए हैं –शासित.

16. उपरोक्त कारणों से, विषय पर कानून को बताने और स्पष्ट करने और आदेश XXI, नियम 89, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही के दायरे को सीमित करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को संशोधित और संशोधित किया गया है।,ऊपर बताए गए क्षेत्र के भीतर। इस अर्थ में, उपरोक्त सीमाओं के भीतर रिमांड के आदेश को बनाए रखते हुए, पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। कोई लागत नहीं।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

भुवनेश सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

नारनौल, हरियाणा

(1) A.I.R. 1930 Madras 921

(2) A.I.R. 1935 Madras 842.

(3) A.I.R. 1953 Tram Cochin 529

(4) A.I.R. 1935 Lahore 51.

(5) A.I.R. 1957 Travencore Cochin 107,

(6) A.I.R. 1975 S.C. 957.

(7) A.I.R. 1940 Patna 191.